



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 5, 2012/आषाढ़ 14, 1934

No. 157]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 5, 2012/ASADHA 14, 1934

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 25 जून, 2012

सं. टीएएमपी/38/2010-एमओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा आदेश सं. टीएएमपी/38/2010-एमओपीटी, दिनांक 18 फरवरी, 2011 को रद्द करता है, जो दिनांक 27 अप्रैल, 2011 को भारत के राजपत्र में राजपत्र संख्या 84 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था, जैसा कि इसके साथ संलग्न आदेश में दिया गया है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

केस सं. टीएएमपी/38/2010 एमओपीटी

मोरमुगाव पत्तन न्यास

आवेदक

आदेश

(जून, 2012 के 18वें दिन पास किया गया)

इस प्राधिकरण ने अपने आदेश संख्या टीएएमपी/23/2008-एमओपीटी दिनांक 7 अगस्त, 2008 के अंतर्गत मोरमुगाव पत्तन न्यास (एमओपीटी) में कोयला संचालन दर्मिनल के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क सीमा निर्धारित की थी। यह आदेश भारत के राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2008 को राजपत्र संख्या 141 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था।

2.1 अपफ्रंट प्रशुल्क दिशा-निर्देशों, 2008 के उपबंध 2.2 में यह विनिर्धारित है कि विभिन्न जिन्सों के संचालन के लिए अथवा पत्तन के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए जब एक बार प्रशुल्क संबंधी

दिशा-निर्देश निश्चित हो जाते हैं जो वे सभी टर्मिनलों पर लागू होंगे, जो कि तदनुसूची जिसमें संचालन के लिए अथवा इसी प्रकार की सेवाओं को प्रदान करने के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान उसी पत्तन में बाद में बोली लगाए जाते हों। तथापि, एमओपीटी ने सीपीटी के माध्यम से विकसित किए जाने वाले बर्थ सं०-11 में कोयले के संचालन के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए जून, 2010 में एक अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्योंकि एमओपीटी का प्रस्ताव, अपफ्रंट प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के उपबंध 2.2 के अनुरूप पाया गया था, तथापि, जहाज मंत्रालय को हस्तगत दिनांक 14 जुलाई, 2010 के पत्र के अंतर्गत संदर्भ भेजा गया था कि वह अध्ययन करके सलाह दे कि क्या कोयला टर्मिनल के लिए एक और अपफ्रंट प्रशुल्क का सेट निर्धारित करने के लिए एमओपीटी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए।

2.2 इसके जवाब में, जहाज मंत्रालय ने अपने पत्र सं० पीडी-25021/6/2010-एमओपीटी दिनांक 4 नवम्बर, 2010 के तहत अपफ्रंट प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के उपबंध 2.2 के संशोधनों को आस्थगित करते हुए, कार्गो के लिए विभिन्न पैरामीटरों एवं लागत संबंधी घटकों को तथा विभिन्न सेवा संबंधी शर्तों को ध्यान में रखते हुए, एमओपीटी के बर्थ सं०-11 में प्रस्तावित कोयला टर्मिनल के लिए अलग से अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारित करने पर विचार करने की सलाह दी थी। मंत्रालय ने यह प्रकाश डाला था कि गोवा राज्य प्रदूषण बोर्ड तथा बम्बई के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में ढके हुए डोमों में कार्गो के भंडारण एवं संचालन के कारण तथा कनवेयर प्रणाली के कारण बर्थ सं०-7 की परियोजनागत लागत की तुलना में बर्थ सं०-11 की परियोजनागत लागत काफी अधिक होगी। गुंबद के आकार की केवल भंडारण सुविधा की लागत लगभग 192 करोड़ रुपए होगी, जिसके परिणामस्वरूप कोयले के भंडारण की लागत में वृद्धि होगी।

2.3 जहाज मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह के अनुपालन में इस प्राधिकरण ने सामान्य परामर्श प्रक्रिया को अपनाते हुए बर्थ सं०-11 में कोयले के संचालन के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क सीमा निर्धारित करने के लिए एमओपीटी के दिनांक 21 जुलाई, 2010 के प्रस्ताव को निपटा दिया था। संबंधित आदेश सं० टीएएमपी/38/2010-एमओपीटी दिनांक 18 फरवरी, 2011 भारत के राजपत्र में राजपत्र सं०-84 के अंतर्गत दिनांक 27 अप्रैल, 2011 को अधिसूचित किया गया था तथा सर्वसंबंधितों को सूचित किया गया था।

3.1 एमओपीटी ने अपने पत्र सं० सी ई/डब्लू के एस/पी सी-38/1013 दिनांक 14 मई, 2012 के अंतर्गत प्रस्ताव दिया था कि बर्थ सं०-11 को तथा प्रशुल्क को भी अपनाया जाए, जो पहले अगस्त, 2008 में अनुमोदित किया गया था तथा दिनांक 18 फरवरी, 2011 के बाद के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया था। इसने बर्थ सं०-11 परियोजना के लिए भी 2008 की अधिसूचना को अपनाने के संबंध में पुष्टि चाही थी।

3.2 उक्त अनुरोध करते समय, एमओपीटी ने दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 को सचिव (जहाज) द्वारा की गई बैठक को भी संदर्भित किया था तथा इंगित किया था कि बर्थ सं०-11 परियोजना पर पुनर्विचार किया गया है एवं पहले प्रस्तावित 4 संख्या वाले डोमों के बजाए 2 शैडों को ढकी हुई भंडारण सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा। संशोधित परियोजनागत लागत एवं क्षमता क्रमशः 204 करोड़ रुपए एवं 2.33 मी. टन होगी, जबकि मूल परियोजनागत लागत 425 करोड़ रुपए एवं क्षमता 4.4 मी. टन प्रति वर्ष थी।

4.1 जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि बर्थ सं0-11 के लिए अलग से अपफ्रंट प्रशुल्क का सेट निर्धारित करना, 2008 के प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था किन्तु उच्च लागत वाले डोमों एवं कनवेयर प्रणालियों के प्रावधान के कारण उक्त परियोजना के लिए उच्च पूंजीगत लागत के विचार से मुख्यतः निर्धारण किया गया था। मंत्रालय के सुझाव पर एमओपीटी ने परियोजना पर अब पुनर्विचार किया है तथा भंडारण के लिए डोम संरचना को शामिल नहीं किया गया है जिससे पूंजीगत लागत 204 करोड़ रु0 कम हो गई है। बर्थ सं0-11 के लिए पूंजीगत लागत में सार्थक परिवर्तन को देखते हुए, उक्त परियोजना के लिए अलग से दर निर्धारित करने के अपने पूर्व-निर्णय की समीक्षा करना जरूरी हो गया है।

4.2 क्योंकि 2008 के प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के उपखण्ड 2.2 बहुत स्पष्ट है तथा वह संरचना इस समय अस्तित्व में नहीं है, जिसके आधार पर दिनांक 18 फरवरी, 2011 का दूसरा प्रशुल्क आदेश पास किया गया था, अतः यह प्राधिकरण, एमओपीटी के अनुरोध पर विचार करने के लिए प्रवृत्त हुआ है तथा उक्त आदेश को रद्द करता है।

5. इसके परिणामस्वरूप, दिनांक 7 अगस्त, 2008 का आदेश एमओपीटी में विकसित की जाने वाली कोयला संचालन परियोजनाओं पर आदेश की अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा, जैसा कि प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के उपबंध 2.2 द्वारा प्रकल्पित किया गया है।

रानी जाधव, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/143/12/असा.]

### TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 25th June, 2012

**No. TAMP/38/2010-MOPT.**—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby cancels the order No. TAMP/38/2010-MOPT, dated 18th February, 2011 which was notified in the Gazette of India on 27th April, 2011 *vide* Gazette No. 84, as in the Order appended hereto.

### TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/38/2010-MOPT

Mormugao Port Trust

Applicant

### ORDER

(Passed on this 18th day of June, 2012)

This Authority fixed upfront tariff caps for coal handling terminal at Mormugao Port Trust (MOPT) vide its Order No. TAMP/23/2008-MOPT dated 7 August 2008. This Order was notified in the Gazette of India on 20 August 2008 vide Gazette No. 141.

2.1. Clause 2.2 of the upfront tariff guidelines, 2008 stipulates that once tariff guidelines are set for handling different commodities or providing various services for a Port, they would apply to all terminals that are bid out subsequently in the same Port during the next 5 years for handling identical commodities or for providing similar services. The MOPT, however, filed a separate proposal in June 2010 for fixing upfront tariff at coal handling at berth no.11 to be developed on PPP mode. Since the proposal of MOPT was found to be not in line with clause 2.2.

of the upfront tariff guidelines, a reference was made to the Ministry of Shipping vide our letter dated 14 July 2010 to examine and advise whether the proposal filed by MOPT for fixing another set of upfront tariff for coal terminal should be considered.

2.2. In response, the Ministry of Shipping vide its letter No. PD-25021/6/2010 – MOPT dated 4 November 2010 advised to consider fixing separate upfront tariff for proposed coal terminal at berth no.11 of the MOPT keeping in view of the different parameters and cost components as well as different service conditions for the cargo, pending amendments to clause 2.2. of the upfront tariff guidelines. The Ministry has also highlighted that the cost of the project at berth no.11 would be substantially higher viz-a-viz the project cost of berth no.7 mainly on account of storage and handling of cargo in covered domes and conveyor system in compliance with the direction of the Goa State Pollution Control Board and Hon'ble High Court of Bombay. The cost of dome storage facility alone would be around ₹ 192 crores resulting in escalation in the cost of storage of coal.

2.3. In compliance with the advice rendered by the Ministry of Shipping, this Authority disposed off the proposal of MOPT dated 21 July 2010 for fixing upfront tariff caps for coal handling at berth no.11, after following the usual consultation process. The relevant Order No. TAMP/38/2010-MOPT dated 18 February 2011 was notified in the Gazette on 27 April 2011 vide Gazette No. 84 and conveyed to all concerned.

3.1. The MOPT vide its letter no. CE/WKS/PC-38/1013 dated 14 May 2012 has proposed to adopt for berth no. 11, also the tariff which was earlier approved in August 2008 and requested for withdrawal of the subsequent Order dated 18 February 2011. It has sought a confirmation about adoption of the notification of 2008 for berth no. 11 project also.

3.2. While making the above request, the MOPT has referred to the meeting taken by Secretary (Shipping) on 13 December 2011 and indicated that berth no. 11 project has been recast and 2 nos. of sheds would be developed as covered storage facility instead of 4 nos. of domes proposed earlier. The revised project cost and capacity would be ₹ 204/- crores and 2.33 MT p.a. respectively as against the original project cost of ₹ 425/- crores and capacity of 4.4 MT p.a.

4.1. As pointed out earlier, fixation of a separate set of upfront tariff for berth no. 11 was not in line with the tariff guidelines of 2008, but was primarily driven by the consideration of the higher capital cost for the said project on account of provision of the high cost domes and conveyor systems. At the instance of the Ministry, the MOPT has now recast the project and excluded the dome structure for storage which has brought down the capital cost to ₹ 204 crores. In view of the significant change in the capital cost for berth no. 11, it may be necessary to review its earlier decision of fixing separate rate for the said project.

4.2. Since clause 2.2 of the tariff guidelines of 2008 is very clear and the premises based on which the 2<sup>nd</sup> tariff order of 18 February 2011 was passed no longer exist, the Authority is inclined to consider the request of MOPT and cancels the said order.

5. Consequently, the Order dated 7 August 2008 will apply to coal handling projects to be developed at MOPT for a period of 5 years from the date of notification of that Order, as envisaged by clause 2.2 of the tariff guidelines.

RANI JADHAV, Chairperson  
[ADVT. III/4/143/12/Ext.]